साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 16 अगस्त 2021, वर्ष-7, अंक-20

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 8 रुपए

संसद में सरकार ने बताया-देश में कितने किसानों ने दी जान

शिव-राज में घटी किसान आत्महत्या

अरविंद मिश्र। भोपाल

सड़क से लेकर संसद तक किसानों का मुद्दा सुर्खियों में है। दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच संसद में भी किसानों के मुद्दे पर पक्ष-विपक्ष आमने-सामने हैं। संसद में घमासान के बीच केंद्र सरकार ने किसानों के आत्महत्या से जुड़े आंकड़े पेश किए हैं, जिससे पता चलता है कि साल 2017, 2018 और 2019 में किन राज्यों में कितने किसानों ने आत्महत्या की है। ये आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट पर आधारित हैं। संसद में पेश रिपोर्ट के अनुसार किसानों की आत्महत्या के मामले में 2017 और 2018 में मप्र जहां टॉप 5 राज्यों में शामिल था। वहीं अब किसानों की आत्महत्या के मामले में टॉप-टेन राज्यों में सातवें नबर पर आ गया है। आंकड़ों में दावा किया किया गया है कि मप्र में वर्ष 2017 में 429, 2018 में 303 और 2019 में 142 किसानों ने आत्महत्या की है। रिपोर्ट में किसानों की आत्महत्या के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि, सरकार का कहना है कि इन आत्महत्या के कारणों में पारिवारिक समस्याएं, बीमारी, नशाखोरी, विवाह संबंधी मुद्दे, प्रेम संबंध, दिवालियापन या कर्ज में डूबना, बेरोजगारी और संपत्ति विवाद हैं।

» टॉप पांच राज्यों से अब 7वें नंबर पर आ गया मप्र

» महाराष्ट्र पहले, कर्नाटक दूसरे व आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर

दस राज्यः वर्षवार मौत के आंकड़े

राज्य	2017	2018	2019
महाराष्ट्र	2426	2239	2680
कर्नाटक	1157	1365	1331
आंध्र प्रदेश	375	365	628
तेलंगाना	846	900	491
पंजाब	243	229	239
छत्तीसगढ़	285	182	233
मध्यप्रदेश	**429**	**303**	**142**
उत्तर प्रदेश	110	80	108
मिजोरम	00	17	22
केरल	42	25	22

2017-18 में मप्र भी टॉप 5 में रहा

साल 2017 में किसानों के आत्महत्या के ममाले में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद तेलंगाना (846), मध्य प्रदेश (429) और आंध्र प्रदेश (375) का नाम शामिल है। वहीं, साल 2018 में इस मामले में तीसरे नंबर पर तेलंगाना (900), चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश (365) और पांचवें नंबर पर मध्य प्रदेश (303) रहा।

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आत्महत्या

रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा आत्महत्या के मामले महाराष्ट्र से हैं। यहां तक कि तीनों वर्षों में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसानों के आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर कर्नाटक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। यही दो ऐसे राज्य हैं जहां तीनों वर्षों में 1000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र में 2017 में 2426, 2018 में 2239 और 2019 में 2680 किसानों ने आत्महत्या की। वहीं, कर्नाटक में 2017 में 1157, 2018 में 1365 और 2019 में 1331 किसानों की आत्महत्या के केस सामने आए।

आंध्र प्रदेश में दोगुने हुए केस

आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है, जहां 2018 के मुकाबले 2019 में किसानों की आत्महत्या के मामले दोगुने हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में 2018 में 375 किसानों ने आत्महत्या की थी, जबकि 2019 में ये आंकड़ा बढ़कर 628 हो गया है। **5वें नंबर पर पंजाबः** साल 2019 में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद सबसे ज्यादा किसानों के आत्महत्या के मामले में तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, चौथे पर तेलंगाना और 5वें नंबर पर पंजाब का नाम आता है। आंध्र प्रदेश में किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा 628, तेलंगाना में 491 और पंजाब में 239 है।

प्रदेश के 81.18 लाख किसानों के खाते में आई सम्मान निधि

भोपाल। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हाल ही में 9वीं किस्त जारी की। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त जमा की। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। योजना के तहत देश के 9.75 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 19,508 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने किसानों से संवाद भी किए। वहीं मध्य प्रदेश के 81 लाख 18 हजार किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 1623 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर किए। मोदी ने बताया कि बीते 7 सालों में कृषि बजट 512 प्रतिशत यानी 5 गुना बढ़ा है। 2013-14 में ये 21 हजार 933 करोड़ रुपए था, जो 2020-21 में बढ़कर 1 लाख 34 हजार 399 करोड़ रुपए हो गया है।

» योजना के तहत 2000 रुपए प्रति किसान किए गए ट्रांसफर

» प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की योजना की 9वीं किस्त

» देशभर के 9.75 करोड़ किसानों को मिला फायदा

इनका कहना है

किसानों की आय दोगुना करने व कृषि क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने प्रधानमंत्री सदैव कार्यरत हैं। आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2000 रुपए प्रति किसान ट्रांसफर की गई, जिससे मध्य प्रदेश के 81.18 लाख कृषक भाई लाभान्वित हुए। मैं मध्य प्रदेश के समस्त किसानों की ओर से प्रधानमंत्री के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं।

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

भोपाल में खुलेगा देश का पहला पारंपरिक औषधि केंद्र!

» प्राचीन आयुर्वेद पद्धतियों पर होगा शोध

» विशनखेड़ी में 11 एकड़ जमीन के लिए भेजा प्रस्ताव

» आयुष विभाग के अफसरों को पसंद आई जगह

विशेष संवाददाता। भोपाल

भारत के पास आयुर्वेद चिकित्सा की बहुत बड़ी विरासत है। इसके चलते ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाकर इसमें पुरानी आयुर्वेद, यूनानी पद्धति पर रिसर्च की जाएगी और इसे आधुनिक भारत की जरूरत के हिसाब से विकसित किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। मप्र सरकार ने इसे लेकर पहल करते हुए भोपाल में इसे बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। यह प्रस्ताव केंद्र की मंजूरी के लिए भेजा गया है। इधर, दूसरी तरफ राजधानी में पांच जमीन इस पारंपरिक औषधि केंद्र के लिए तलाशी गई थी, जिसमें से एक जगह आयुष विभाग के अफसरों को पसंद भी आ गई है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो विशनखेड़ी में 11 एकड़ पर डब्ल्यूएचओ के सहयोग से यह पारंपरिक औषधि केंद्र खुल सकता है। इसके लिए जमीन आवंटन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया गया है।

चल रहा विशेष अभियान

पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को विकसित करने के लिए 2014 से 2023 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह औषधि केंद्र इसी अभियान का हिस्सा है। डब्ल्यूएचो के महानिदेशक टेड्रोस एडहैनम घेब्रेयसस ने विगत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस तरह के सेंटर को स्थापित करने के लिए आग्रह किया था।

आयुर्वेद पर फोकस

कोरोना महामारी के दौरान भारत के आयुर्वेद का ज्ञान दुनिया के लिए काफी मददगार साबित हुआ। भारत की नई शिक्षा नीति में एलोपैथी के डॉक्टर को आयुर्वेद तथा आयुर्वेद के डॉक्टर को एलोपैथी का ज्ञान दिए जाने की बात भी चल रही है।

इसलिए मप्र सबसे बेहतर

मप्र में जनजातीय क्षेत्र और सघन वन अधिक हैं, जहां पर प्रचुर मात्रा में औषधीय पौधे और जड़ी-बूटियां आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। इन पर देश-विदेश के लोग यहां आकर रिसर्च कार्य कर सकते है और पुरानी पद्धति से होने वाले इलाज को और अधुनिक युग के हिसाब से विकसित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, भोपाल को ही चुनने के पीछे कारण यह भी है कि यहां पहले से ही खुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज, यूनानी व होम्योपैथी कॉलेज सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा यहां एम्स और गांधी मेडिकल कॉलेज भी है। लिहाजा शोध करने के लिए डॉक्टर और छात्रों की जरूरत आसानी से पूरी हो सकती है।

» बाढ़ से 8 तरह का नुकसान, 5 में मुआवजे का प्रावधान, 3 के लिए नियम ही नहीं

» ग्वालियर-चंबल के बाढ़ प्रभावित जिलों के कलेक्टरों ने सरकार से मांगा मार्गदर्शन

» साहब! नई कॉलोनी बसा दो...वरना खाली कर देंगे गांव...मुश्किल से बची जान

» शिवपुरी कलेक्ट्रेट पहुंच बाढ़ प्रभावित अपनी पीड़ा सुनाते अफसरों से बोले

» जिनके पशु बाढ़ में बए गए उन्हें नहीं मिलेगी आर्थिक मदद!

» आरबीसी 6-4 में नहीं है आर्थिक सहायता का प्रावधान

असमंजस में मुआवजा

खेमराज मौर्य, शिवपुरी

ग्वालियर-चंबल के कई गांवों में आई बाढ़ ने लोगों का जीवन उजाड़ दिया है। कुदरत की आफत के बाद कई लोग ऐसे हैं, जिन्हें अब भी मदद का इंतजार है। ऐसा ही दर्द शिवपुरी जिला मुख्यालय से महज 12 किमी दूर नीमदांड़ा गांव के लोगों का भी है। न उनके सिर पर छत बची है, न खाने को खाना है। सोने के लिए बिछौना तक नहीं है और वे पत्थर पर सोने को मजबूर हैं। इधर, शिवपुरी जिला पंचायत के सीईओ एचपी वर्मा का कहना है कि प्रभावित गांवों में बाढ़ राहत का राशन पहुंचाया जा रहा है और जहां नहीं पहुंच पा रहा है, वहां जल्द से जल्द पहुंचाया जाएगा। वहीं ग्वालियर-चंबल संभाग के आठ जिलों में आई बाढ़ में लोगों को हुए नुकसान का मुआवजा पूरा मिलेगा या नहीं, इसे लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हो सकी है। वजह-बाढ़ में लोगों को 8 तरह का नुकसान हुआ है, इनमें से पांच तरह की क्षति में मुआवजा देने का प्रावधान आरबीसी 6-4 यानी राजस्व पुस्तक परिपत्र में दर्ज है। इस बार तीन तरह की क्षति ऐसी हुई हैं जिनमें मुआवजे का प्रावधान नहीं लिखा है। इस कारण बाढ़ प्रभावित जिलों के कलेक्टर अब राजस्व विभाग से मार्गदर्शन मांगने के साथ सुझाव व प्रस्ताव भेज रहे हैं, ताकि हर नुकसान की क्षतिपूर्ति दी जा सके। शिवपुरी कलेक्टर ने सर्वाधिक तीन नए प्रस्ताव और सुझाव सरकार को भेजे हैं। यदि ये सुझाव माने गए तो बाढ़ में हुए हर तरह के नुकसान की भरपाई हो सकेगी। नुकसान के संबंध में तीन नए प्रस्ताव भेजने की पुष्टि जिला पंचायत सीईओ एचपी वर्मा ने भी की है।

आहत को राहत

शिवपुरी में बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंच रहीं खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया। वो उन्हें राहत सामग्री भी बांट रही हैं। यही नहीं, सरकारी अमले को भी ताकीद कर रही हैं कि प्रभावितों की परेशानी को गंभीरता से लिया जाए। उनका कहना है कि यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समय रहते हेलीकॉप्टर एवं अन्य राहत सामग्रियां अगर उपलब्ध न कराई होतीं तो स्थिति बदतर हो जाती।

रास्ता निकालेंगे शिवराज

राजस्व विभाग ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अवगत करा दिया है। संभवतः अगली होने वाली कैबिनेट बैठक में सरकार बाढ़ में लापता होने वाले पुशओं के नुकसान की भरपाई का कोई रास्ता निकाल सकती है। ग्वालियर-चंबल के 8 जिलों में 30 हजार से ज्यादा पशुहानि का आंकलन है। नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। जिनके घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, उन्हें 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी मिलने लगी है।

बारिश ने तोड़ा मनोबल

वहीं बैराढ़ तहसील में पार्वती नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ ने ग्रामीण परिवारों को पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया है। सिलपरी और कुपरेड़ा गांव के ग्रामीण ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से शिवपुरी कलेक्टोरेट पहुंच गए। खासतौर पर सिलपरी के ग्रामीण गांव खाली करने की बात किए। ग्रामीणों ने कहा कि इस बार बाढ़ में बमुश्किल जान बची है। नीचे से बाढ़ का पानी और ऊपर से लगातार बरसते पानी ने ग्रामीणों का मनोबल पूरी तरह तोड़कर रख दिया है। ग्रामीण मनोज ने बताया कि बाढ़ ने गृहस्थी बर्बाद कर दी है, अब भूखों मरने की स्थिति बनने लगी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से गेहूं का एक कट्टा जरूर मिला है। लेकिन इसके सहारे कब तक पेट भर पाएंगे।

फसल भी बर्बाद

भौराना ग्राम पंचायत में आने वाले कुपरेड़ा गांव के ग्रामीणों ने अलग ज्ञापन दिया है। ग्रामीणों ने कहा अतिवृष्टि के कारण हमारी फसल पूरी तरह गलकर नष्ट हो गई है। आवासीय मकान, पालतू मवेशी व गृहस्थी का सामान, गेहूं, चना आदि उपज भी नष्ट हो गई है। भूखों मरने की स्थिति पैदा हो गई है। आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। सिलपरी और कुपरेड़ा गांव पार्वती नदी की बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए अलग से कॉलोनी काटकर स्थापित किया जाए।

200 परिवार बर्बाद

ग्रामीणों ने प्रशासन से यह भी मांग की कि अलग से फॉरेस्ट की जमीन पर कॉलोनी काटी जाए। यह जगह बाढ़ की चपेट में नहीं आती। वहीं शबनम जाटव ने बताया कि सिलपरी गांव में बाढ़ और अतिवृष्टि से 150 से 200 परिवार बर्बाद हो गए। एक बुजुर्ग ने बताया कि जीवन में ऐसी बाढ़ कभी नहीं देखी। चारों तरफ पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था, ऊपर से लगातार पानी बरस रहा था। यह देखकर लगा कि अब कोई नहीं बच पाएगा।

पशुओं की डूबने से मौत

मुआवजा: नियम के तहत पशु के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। छोटे पशु पर 10 हजार और बड़े पशु की मौत पर 30 हजार रुपए मुआवजा मिलेगा।

फसल खराब होना

मुआवजा: सर्वे के बाद हर तरह की फसल में नुकसान का आकलन कर क्षतिपूर्ति देने का नियम है। प्रति हेक्टेयर 30 हजार रुपए तक मुआवजा दिया जा सकता है।

घर टूटना

मुआवजा: सर्वे के बाद आंशिक और पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान या झोंपड़ी के बदले में मुआवजा दिया जा सकता है। यह राशि इस बार 1.20 लाख रुपए घोषित की गई है।

इन के लिए मांगा मार्गदर्शन

पशु बहे और शव नहीं मिले

मुआवजा: अभी तक प्रावधान नहीं, इसके लिए सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया है। अलग-अलग जिलों में बाढ़ में बहने वाले पशुओं के लापता होने की एफआईआर दर्ज कराकर पंचनामा बनवाए जा रहे हैं। ग्वालियर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के एसडीएम ने इस बारे में वरिष्ठ अफसरों से इसके लिए मार्गदर्शन मांगा है।

घर में रखा अनाज भी सड़ गया

मुआवजा: अभी तक इस तरह के नुकसान का आकलन नहीं किया जाता। इस बार ऐसा कई गांवों में हुआ है, जब किसानों के घरों में रखा गेहूं या दूसरा अनाज बाढ़ के पानी में डूबने से सड़ गया। किसान इस अनाज को सड़कों पर रखकर सुखा रहे हैं। इसके लिए सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया है।

खेतों से उपजाऊ मिट्टी बह गई

मुआवजा: बाढ़ में 1.11 लाख हेक्टेयर में फसलें खराब हुई हैं। खेतों की उपजाऊ मिट्टी को बाढ़ बहाकर ले गई। खेत बंजर हो गए हैं जिनमें बीज नहीं बोया जा सकता है, लेकिन इस नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए न सर्वे किया जाता न ही कोई नियम है। इसके लिए भी सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया है।

मंदिर में बिता रहे रात

गांव के लोगों को पत्थर रख कर सोना पड़ रहा है। कुछ ग्रामीण बताते है कि बाढ़ में उनका सब उजड़ चुका है। खाने-पीने की भी व्यवस्था नहीं है। हम लोग मंदिर में रात बिता रहे हैं। कोई सरकारी मदद भी नहीं पहुंची है। कंट्रोल से पैसे देकर गेहूं खरीद रहे हैं। नारायणी और रामखिलावन ने बताया कि सड़क पूरी तरह से बह चुकी है। लोगों ने सड़क पर मिट्टी रखकर खुद जुगाड़ का रास्ता बनाया है।

घरों में बाढ़ से आई मिट्टी: इधर, बाढ़ के कारण नीमदांड़ा गांव से होकर मझेरा गांव जाने वाली सड़क पूरी तरह बह गई है। ग्रामीणों ने आवाजाही के लिए अपने प्रयासों से सड़क के एक हिस्से पर मिट्टी डाल कर अस्थाई व्यवस्था की है। नीमदांड़ा के खेतों तक जाने के लिए अभी भी ग्रामीणों को नदी में उतर कर कमर तक पानी में से होकर जाना पड़ रहा है। घरों के अंदर मिट्टी और दल-दल घुस चुका है।

इनका कहना है

बाढ़ में लोगों को कई तरह का नुकसान हुआ है। आरबीसी 6-4 में वर्णित प्रावधानों के तहत नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसकी तैयारियां की जा रही हैं। जो नुकसान आरबीसी में उल्लेखित नहीं हैं, उनमें कलेक्टरों द्वारा भेजे सुझाव या मार्गदर्शन का परीक्षण करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

-ज्ञानेश्वर बी पाटिल, सचिव, राजस्व विभाग, मप्र

'आत्मनिर्भर नारी शक्ति' से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संवाद, बोले

12वीं पास चंपा जैविक खेती की 'मास्टर'

जैविक खेती को आनलाइन दें बढ़ावा, सरकार मदद करेगी

भोपाल/नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'आत्मनिर्भर नारी शक्ति' से संवाद कार्यक्रम में वर्चुअली हिस्सा लिए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मास्टर कृषि सखी (सीआरपी) चंपा सिंह से भी संवाद किए। चंपा सिंह ने प्रधानमंत्री से अपने आत्मनिर्भर होने की कहानी बताई। चंपा सिंह जैविक खेती और कृषि तकनीकी के लिए प्रोत्साहन के लिए लंबे समय से काम कर रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि कैसे उन्होंने जैविक खेती कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया। चंपा सिंह ने बताया कि शुरुआत में कुछ समय मुझे संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कृषि सखी बनने के बाद मेरी जान-पहचान बढ़ने लगी। चंपा की बात सुनकर प्रधानमंत्री ने कहा कि चंपाजी, आपने बता दिया कि नारी जब सशक्त होती है तो सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरा समाज सशक्त होता है। चंपा से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने सलाह के रूप में पूर्व में मन की बात के तहत कही गई बातों में चंपा से पूछा क्या आप आनलाइन के जरिए जैविक उत्पाद को आनलाइन के जरिए अभियान चलाकर किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित कर सकती हैं सिखा सकती हैं। संवाद कर टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्ट दोनों काम आनलाइन कर सकती हैं। जिस पर चंपा ने कहा वह पूरी तरह से तैयार हैं तब प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको ऑनलाइन किया जाएगा। जिससे देश के किसानों को मदद मिल सके।

स्थानीय उत्पादों पर फोकस

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार वो माहौल, वो स्थितियां बना रही है जहां से सभी बहनें हमारे गांवों को समृद्धि और संपन्नता से जोड़ सकती हैं। भारत में बने खिलौनों को भी सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही हैं, इसके लिए हर संभव मदद भी दे रही है। विशेष रूप से हमारे आदिवासी क्षेत्रों की बहनें तो पारंपरिक रूप से इससे जुड़ी हैं। इसमें भी बहुत संभावनाएं हैं। आज देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का अभी अभियान चल रहा है। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की दोहरी भूमिका है। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जागरूकता भी बढ़ानी है और इसके विकल्प के लिए भी काम करना है। आज देशभर में लगभग 70 लाख स्वयं सहायता समूह हैं, जिनसे लगभग 8 करोड़ बहनें जुड़ी है।

गांव की बेटी बनी रोल मॉडल

गौरतलब है कि चंपा सिंह मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले की रहने वाली हैं और कम लागत वाली कृषि तकनीकी व जैविक कृषि प्रोत्साहन के लिए कार्य कर रही हैं। जिले में 12वीं पास चंपा सिंह अपनी मेहनत के कारण महिला सशक्तिकरण की पर्याय बन चुकी हैं। जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील के एक छोटे से गांव में रहने वाली चंपा ने कम समय में जो सफलता हासिल की, वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती हैं, यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें संवाद करने का मौका मिला।

खेत की बढ़ गई उर्वरा शक्ति

प्रधानमंत्री चंपा से संवाद करते हुए चलाई जा रही दुकान के बारे में पूछा जिस पर चंपा ने कहा कि यह दुकान गांव के बाजार में हर सप्ताह हर दिन खुलती है और यहां आकर लोग जैविक खेती में उपयोग किए जाने वाले खाद कीटनाशक दवा के बारे में सलाह लेते हैं और खरीद कर ले जाते हैं। जिससे समूह को अच्छी आमदनी हो रही है और खेती की उर्वरा शक्ति बढ़ गई है। खाद और दवा दोनों घर पर ही हम तैयार करते हैं।

1600 करोड़ रुपए की राशि भेजी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना में जिस प्रकार से हमारी बहनों ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से देशवासियों की सेवा की वो अभूतपूर्व है। मास्क और सैनिटाइजर बनाना हो, जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाना हो, जागरूकता का काम हो, हर प्रकार से आपकी सखी समूहों का योगदान अतुलनीय रहा है। महिलाओं में उद्यमशीलता का दायरा बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में अधिक भागीदारी के लिए आज बड़ी आर्थिक मदद जारी की गई है। फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यम हो, महिला किसान उत्पादक संघ हो या फिर दूसरे स्वयं सहायता समूह, बहनों के ऐसे लाखों समूहों के लिए 1,600 करोड़ रुपए से अधिक राशि भेजी गई है। आजादी के 75 वर्ष का ये समय नए लक्ष्य तय करने और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का है।

कई राज्यों में सहयोग कर चुकीं चंपा

चंपा सिंह कई राज्यों में कृषि सखी के रूप में कृषकों की मदद भी कर चुकी है और समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर हुई हैं। उन्होंने अपने गांव, जिला, प्रदेश के साथ अन्य प्रदेशों में भी आजीविका सुदृढ़ीकरण के लिए उन्नत कृषि तकनीक, जैविक पद्धति को अपनाने के लिए समूह सदस्यों और कृषकों को जागरुक किया है। चंपा सिंह अपने संघर्ष, सफलता से जुड़े किस्से बताकर दूसरों को प्रेरित करना चाहती हैं।

मप्र में 25 फीसदी घटा सोयाबीन का रकबा

- » पैदावार भी कम होने की आशंका
- » नुकसान के चलते किसानों ने सोयाबीन छोड़ धान को अपनाया
- » मौसम का दुष्प्रभाव और कीट प्रकोप भी देने लगा दिखाई

संवाददाता, भोपाल

बंपर पैदावार के चलते मप्र को ख्याति दिलाने वाली सोयाबीन फसल से अब किसानों का मोह भंग हो गया है। लगातार नुकसान झेल रहे किसान अब धान, उड़द और अरहर की खेती में रुचि लेने लगे हैं। इस बार प्रदेश में सोयाबीन का रकबा करीब 25 फीसदी घट गया है। वहीं मौसम के दुष्प्रभाव और कीट प्रकोप की मार झेल रहे सोयाबीन की पैदावार भी इस साल 50 फीसदी घटने की आशंका जताई जा रही है। इसका असर सोयाबीन तेल के दामों में बढ़ोतरी के रूप में दिखाई दे सकता है। दस साल पहले तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में काफी सोयाबीन बोया जाता रहा, लेकिन मौसम की मार और पैदावार में कमी से यह घाटे का सौदा बनने लगा। पिछले साल अतिवर्षा के कारण प्रदेश में सोयाबीन फसल को काफी नुकसान हुआ था। इस वजह से इस बार किसानों को बीज भी मुश्किल से मिला और दाम भी दोगुना से अधिक रहे। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सोयाबीन की पैदावार प्रति हेक्टेयर 18 से 20 क्विंटल मानी जाती रही है, लेकिन पांच वर्षों के दौरान यह घटकर आठ से 10 क्विंटल तक पहुंच गई है। जबकि लागत हर साल बढ़ती रही।

धान का बढ़ा रकबा

कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में बीते साल 66,73,869 हेक्टेयर में सोयाबीन की बोवनी हुई थी। इस साल इसका रकबा 50,05,402 हेक्टेयर रह गया है यानी इसमें पिछले साल के मुकाबले 25 फीसदी की गिरावट आ गई है। पिछले साल की तुलना में धान का रकबा 44 फीसदी बढ़ गया है। वर्ष 2018-2019 तक मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। उस वक्त सालाना पैदावार 67 लाख टन के करीब थी। वर्ष 2019-2020 में यह घटकर 49 लाख टन रह गई। वर्ष 2020-2021 में पैदावार 51 लाख टन रही। इस बार खराब मौसम और कीट प्रकोप से पैदावार में काफी कमी आ सकती है। सोयाबीन की पैदावार कम होने की मुख्य वजह किसानों ने फसल में रोटेशन सिस्टम नहीं अपनाया। एक ही फसल बोते रहे। जमीन की उर्वरा शक्ति लगातार कम होती रही। इससे कीट प्रकोप भी बढ़ता गया।

सोयाबीन तेल होगा महंगा

कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि तलरेजा बताते हैं कि पिछले एक साल में सोयाबीन तेल की कीमत में 53 रुपए प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। सोयाबीन की पैदावार घटने से तेल के दाम दस फीसद तक फिर बढ़ सकते हैं।

इनका कहना है

प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से सोयाबीन किसानों के लिए घाटे का सौदा बन गई है। किसान विकल्प के तौर पर धान, उड़द और अरहर की खेती में रुचि दिखा रहे हैं। यह अच्छी बात है। जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए भी फसल परिवर्तन जरूरी था। लेकिन सोयाबीन का घटता रकबा चिंता का विषय है। लगातार 30 साल से वही बीज बोने के कारण इसमें बीमारी बढ़ रही है। इस वजह से वर्तमान में प्रदेश में सोयाबीन का 20 फीसदी रखबा कम हो गया है। इस समस्या से निपटने के लिए कृषि वैज्ञानिकों के साथ मिलकर सोयाबीन का विकल्प तलाशा जा रहा है।

कमल पटेल, कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

किसानों का कल्याण केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता

शोभा करांदलाजे,
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री

देश में विकास के सात दशक बाद भी कृषि का महत्व अपनी जगह कायम है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों को कच्चे माल की आपूर्ति इसी क्षेत्र से होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को हालांकि दशकों पहले लाइसेंस राज से मुक्ति मिल गई, मगर कृषि का क्षेत्र 1991 के सुधार के राडार से दूर रहा। कृषि क्षेत्र में शिथिलता बनी रही।

देश में विकास के सात दशक बाद भी कृषि का महत्व अपनी जगह कायम है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों को कच्चे माल की आपूर्ति इसी क्षेत्र से होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को हालांकि दशकों पहले लाइसेंस राज से मुक्ति मिल गई, मगर कृषि का क्षेत्र 1991 के सुधार के राडार से दूर रहा। कृषि क्षेत्र में शिथिलता बनी रही। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि अधिकांश फसलें देश के किसी क्षेत्र विशेष व दूसरे हिस्सों में भी उगाई जाती हैं। फिर भी खाद्य तेल, दलहन और जल्द खराब होने वाले फल व सब्जियों की कमी की पूर्ति के लिए आयात पर निर्भर करना पड़ता है, क्योंकि सुधार के दौर में हरितक्रांति के उत्तर काल में इसे नजरंदाज कर दिया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि कृषि की बुनियादी समस्याओं को दूर करने के लिए नवोन्मेष की आवश्यकता है, जिसका असर अल्पकाल में दिखाई दे। वर्ष 2014 के बाद सरकार ने सुधार के कई कार्यक्रमों को लागू किया, जिससे कृषि क्षेत्र की क्षमता का विकास हुआ है और आज यह क्षेत्र परिवर्तन के पथ पर अग्रसर है। विगत सात साल के दौरान मौजूदा सरकार ने उत्पादन के बजाय किसानों की आमदनी बढ़ाने के कार्यक्रमों को ज्यादा प्रमुखता दी। मुख्य रूप से कृषि उपज की कीमत, बाजारों के एकीकरण, सुरक्षा की व्यवस्था और समावेशी विकास केंद्रित सुधार पर विशेष जोर दिया गया। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में काफी बढ़ोतरी की गई है। इस समय विभिन्न फसलों का एमएसपी उनकी उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना है। न सिर्फ एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि विगत सात साल में किसानों को एमएसपी के तौर पर किए गए भुगतान में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2013-14 से 2020-21 के दौरान एमएसपी के रूप में गेहूं के लिए किसानों को किए गए भुगतान में 121 फीसदी की वृद्धि हुई है, जबकि चावल के लिए किए गए भुगतान में 170 फीसदी का इजाफा हुआ है। दलहन और कपास के मामले में यह राशि 2013-14 के क्रमश: 236 करोड़ और 90 करोड़ से बढ़कर क्रमश: 4,361 करोड़ और 28,760 करोड़ रुपए हो गई है। बीते सात साल में गेहूं और चावल के उत्पादन में जहां क्रमश: 13.89 फीसदी और 13.45 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, वहां केंद्रीय पूल के लिए गेहूं की खरीद में 63.38 फीसदी और चावल की खरीद में 55.40 फीसदी की वृद्धि हुई है। कुछ अन्य फसलों के संबंध में भी उत्पादन की तुलना में सरकारी खरीद की ऐसी ही प्रवृत्ति पाई गई है। रबी विपणन वर्ष 2020-21 में सरकारी खरीद का लाभ पाने वाले किसानों की संख्या में 2019-20 के मुकाबले 20 फीसदी का इजाफा हुआ। गौर करने की बात है कि वर्ष 2020-21 में सेंट्रल पूल के लिए पंजाब और हरियाणा से 87,690 करोड़ मूल्य के धान और गेहूं की खरीद की गई। एमएसपी का भुगतान पहले आढ़तियों व बिचौलिये के खाते में किया जाता था, लेकिन अब सीधे किसानों के बैंक खाते में एमएसपी का हस्तांतरण होने लगा है। बीते सात साल में विभिन्न फसलों के एमएसपी में 40 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी करने के साथ-साथ कीमत स्थिरीकरण कोष के तहत टॉप से लेकर टोटल स्कीम, ऑपरेशन ग्रीन्स, पीएम-आशा के तहत आवंटन में वृद्धि की गई है। साथ ही, किसान रेल और कृषि उड़ान के जरिए कृषि उत्पादों का निर्बाध परिवहन आसान हो गया है। इन पहलों से किसानों को उचित व समतुल्य कीमत दिलाना, सुनिश्चित करने में काफी मदद मिली है। किसनों को बेहतर दाम दिलान के साथ-साथ मौजूदा कीमत नीतियों के तहत पोषण और फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा दिया जाता है। इस प्रकार, पोषक अनाजों के एमएसपी में काफी बढ़ोतरी की गई है, ताकि इन फसलों की खेती को प्रोत्साहन मिले। साथ ही, एमएस स्वामीथन आयोग के सुझावों के अनुरूप विभिन्न बायोफोर्टिफायड फसलों को व्यावसायिक रूप से जारी किया गया है। इसके अलावा, क्षेत्रीय फसल योजना और उत्पत्ति स्थान आधारित फसल पैटर्न की पहचान करने और उसे आवश्यक प्रोत्साहन देने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि स्थानीय दुर्लभ संसाधनों का बेहतर लाभ उठाया जा सके और जलवायु परिवर्तन व प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित प्रभावों को कम किया जा सके। एक जिला एक उत्पाद को प्रोत्साहन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना, केसर पार्क, कृषि के प्रति युवाओं को आकर्षित करना और कृषक उत्पादक संगठन जैसी योजनाएं उत्पति स्थान की संकल्पना के अनुरूप हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम लेपित यूरिया, उर्वरक के लिए डीबीटी और नैनो तरल यूरिया जैसी पहलों का मकसद मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उर्वरकों के संतुलित उपयोग और दक्षता प्रोत्साहन देना है। बीते सात साल में केंद्रीय कृषि मंत्रालय का बजटीय आवंटन व खर्च में काफी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2013-14 में मंत्रालय का बजट 27,040 करोड़ था जो 2021-22 में बढ़कर 1,31,531 करोड़ रुपए हो गया। किसानों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए, पीएम-किसान के साथ-साथ पेंशन स्कीम पीएम-किसान मान-धन योजना लागू की गई है। इसके अलावा, किसानों के सशक्तीकरण के लिए पीएम-कुसुम योजना लागू की गई है। देश के छोटे व सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना काफी मददगार साबित हुई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के साथ-साथ नए कृषि कानून, कृषक उत्पाद व्यापार और वाणिज्य कानून, 2020 और कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून, 2020 लाने के ऐतिहासिक कदम से कृषि के क्षेत्र में सामान्य व्यापार से कहीं ज्यादा तर्कसंगत विविधीकरण के साथ अहम बदलाव देखने को मिल सकता है। कृषि उत्पादों के उदार व्यापार के लिए इससे पहले कोई कानून नहीं था। इसलिए इन कानूनों से कृषि के क्षेत्र में अरसे प्रतीक्षित विकास को रफ्तार मिलेगी और निवेश को बढ़ावा मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव आएगा। कुछ ऐसे क्षेत्रों व विषयों की सूची है, जिन पर कानून बनाने या विनियमन की शक्ति सिर्फ केंद्र सरकार के पास नहीं है। हालांकि पिछले सात वर्षों में, केंद्र सरकार ने नीति आयोग की सक्रिय भागीदारी के साथ विविध मॉडल अधिनियम लाए हैं। मसलन, भूमि पट्टेदारी कानून 2016, एपीएलएम अधिनियम 2017, अनुबंध खेती अधिनियम 2018 व अन्य। इन कानूनों से राज्यों को कृषि व्यापार पर कानून बनाने व उसे विनियमित करने के लिए मॉडल फ्रेमवर्क की आवश्यकता के मद्देनजर राज्यों की मदद करने के लिए ये कानून बनाए गए। कृषि उपज के बेहतर विपणन के लिए 10,000 एफपीओ की स्थापना को सक्रिय रूप प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साथ ही, एग्री-मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्च र फंड के माध्यम से 22,000 ग्रामीण हाटों में मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्च र को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि एपीएमसी को सीधे तौर पर उपलब्ध होता है। कृषि से देश की 50 फीसदी से ज्यादा आबादी सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, इसलिए केंद्र सरकार कृषि सुधारों को सक्रियता के साथ लागू करने वाले राज्यों को उनके निष्पादन के आधार पर 45,000 करोड़ रुपए अनुदान देने पर विचार कर रही है। बीते सात साल में सरकार ने बागवानी, डेयरी, मत्स्यपालन जैसे संबंधित क्षेत्रों में के विकास की पहचान की है, जिसमें सालाना 4-10 फीसदी की सालाना वृद्धि दर्ज की गई है। इन क्षेत्रों का का उद्यम और उसका प्रबंधन मुख्य रूप से लघु व सीमांत समुदायों के हाथों में है, उनको सरकार की तरफ से मदद मिल रही है और नए हस्तक्षेप का आगाज समावेशी विकास की पहचान है। विगत सात साल में लाए गए सुधार से ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी कम करने और समृद्धि लाने की दिशा में प्रगति हुई है।

चावल, गेहूं, दलहन फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। खाद्यान्न का 308.65 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के अथक परिश्रम, वैज्ञानिकों की कुशलता और भारत सरकार की कृषि एवं किसान हितैषी नीतियों से देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है। भारतीय कृषि को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, राज्यों के साथ मिलकर ठोस कार्य कर रही है, जो आगे भी जारी रहेगा। वर्ष 2020-21 के लिए चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 308.65 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2019-20 के उत्पादन की तुलना में 11.14 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2020-21 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन विगत पांच वर्षों (2015-16 से 2019-20) के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 29.77 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2021-22 की प्रमुख फसलों के अनुमानित उत्पादन में खाद्यान्न- 308.65 मिलियन टन, चावल- 122.27 मिलियन टन, गेहूं- 109.52 मिलियन टन, पोषक/मोटा अनाज 51.15 मिलियन टन, मक्का- 31.51 मिलियन टन, दलहन- 25.72 मिलियन टन, तुअर- 4.28 मिलियन टन, चना- 11.99 मिलियन टन, तिलहन 36.10 मिलियन टन, मूंगफली- 10.21 मिलियन टन, सोयाबीन-12.90 मिलियन टन, रेपसीड एवं सरसों- 10.11 मिलियन टन(रिकार्ड), गन्ना 399.25 मिलियन टन, कपास- 35.38 मिलियन गांठें (प्रति 170 किग्रा), पटसन एवं मेस्टा- 9.56 मिलियन गांठें (प्रति 180 किग्रा) है। वर्ष 2020-21 के दौरान चावल का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 122.27 मिलियन टन अनुमानित है। यह विगत पांच वर्षों के 112.44 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.83 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2020-21 के दौरान गेहूं का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 109.52 मिलियन टन अनुमानित है। यह 100.42 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.10 मिलियन टन अधिक है। इसी प्रकार, पोषक/मोटे अनाजों का उत्पादन 51.15 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2019-20 के उत्पादन की तुलना में 3.40 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा, यह औसत उत्पादन की तुलना में भी 7.14 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल दलहन उत्पादन रिकॉर्ड 25.72 मिलियन टन अनुमानित है जो विगत पांच वर्षों के 21.99 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 3.73 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2020-21 के दौरान देश में कुल तिलहन उत्पादन रिकॉर्ड 36.10 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2019-20 के उत्पादन की तुलना में 2.88 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 के दौरान तिलहनों का उत्पादन 30.55 मिलियन टन, औसत तिलहन उत्पादन की तुलना में 5.56 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2020-21 के दौरान देश में गन्ने का उत्पादन 399.25 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2019-20 के दौरान के औसत गन्ना उत्पादन 362.07 मिलियन टन की तुलना में 37.18 मिलियन टन अधिक है। कपास का उत्पादन 35.38 मिलियन गांठें (प्रति 170 किग्रा की गांठे) अनुमानित हैं जो औसत कपास उत्पादन की तुलना में 3.49 मिलियन गांठें अधिक है। पटसन एवं मेस्ता का उत्पादन 9.56 मिलियन गांठें (प्रति 180 किग्रा की गांठे) अनुमानित हैं।

प्रदेश के जन-भागीदारी मॉडल से मिली कोरोना नियंत्रण में सफलता

महेश दुबे
जनसंपर्क अधिकारी

मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण से पार पाने के और प्रदेशवासियों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए जन-भागीदारी का जो मॉडल अपनाया गया, वह अन्य राज्यों के लिए चर्चा का विषय बन गया। इसमें मुख्य रूप से कोरोना सक्रंमण के उपचार की व्यवस्थाओं के साथ जन-जागरूकता संबंधी कार्यों ने महती भूमिका निभाई।

मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण से पार पाने के और प्रदेशवासियों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए जन-भागीदारी का जो मॉडल अपनाया गया, वह अन्य राज्यों के लिए चर्चा का विषय बन गया। इसमें मुख्य रूप से कोरोना सक्रंमण के उपचार की व्यवस्थाओं के साथ जन-जागरूकता संबंधी कार्यों ने महती भूमिका निभाई। कोरोना की पहली और दूसरी लहर से निपटने में रही कमियो को दूर करते हुए संभावित तीसरी लहर के प्रति अधिक सर्तकता और सजगता बरती जा रही है। इन प्रयासों में चिकित्सकीय अधो-संरचनाओं का व्यापक विस्तार के साथ ऑक्सीजन के नवीन प्लांट लगाकर मध्यप्रदेश को आत्म-निर्भर बनाया जा रहा है। प्रदेश में कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण रखने का परिणाम है कि आज की स्थिति में नाम मात्र के 131 सक्रिय कोविड-19 मरीज हैं। नागरिकों ने कोविड-19 अनुकूल व्यवहार को पूरी तरह से अपनाया है। सोशल डिस्टेंसिंग, घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग और बार-बार साबुन अथवा सेनेटाइजर से हाथों को सेनेटाइज करने को अब नागरिकों ने अपनी आदत बना ली है। टीकाकरण महाअभियान से आई जागरूकता का परिणाम है कि प्रदेश देश में पहली डोज के 3 करोड़ 8 लाख टीके लगवाने के बाद कुल लक्ष्य के 50 प्रतिशत से अधिक का टीकाकरण कर देश में अव्वल है। इसके साथ ही कोविड-19 के लक्षणों के दिखने पर अब लोग डरते नहीं है। फीवर क्लीनिक पहुंचकर टेस्ट करवाते हैं। पॉजिटिव होने पर उपचार भी लेते हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में पर्याप्त विस्तार किया गया है। विस्तार का यह क्रम लगातार जारी है। कोरोना के उपचार में सर्वाधिक कारगर ऑक्सीजन को स्वास्थ्य केन्द्रों तक निर्बाध रूप से उपलब्ध कराने के लिये अब ऑक्सीजन की परिवहन पर निर्भरता नहीं रहेगी। प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन के 189 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट बनाए जा रहे हैं। अब तक 57 ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित कर शुरू कर दिए गए हैं। सितम्बर अंत तक सभी 189 प्लांटस् को प्रारंभ कर दिया जाएगा। पीएसए ऑक्सीजन प्लांट सभी चिकित्सा महाविद्यालय और जिला चिकित्सालय में स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें 11 चिकित्सा महाविद्यालय और 83 प्लांट जिला चिकित्सालयों में लगाए जा रहे हैं। सिविल अस्पतालों में 48, सामुदायिक संस्थाओं में 41 और अन्य शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में 6 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट के साथ ही हवा से ऑक्सीजन बनाने वाले पोर्टेबल उपकरण ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर को भी अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में अभी 14 हजार 13 ऑक्सीजन सर्पोटेड बेडस् है। इनको बढ़ाकर सितंबर अंत तक 17 हजार 827 किया जाएगा।

चिकित्सा महाविद्यालयों में वर्तमान में उपलब्ध 3,776 आईसीयू/एचडीयू बेडस् को सितंबर तक बढ़ाकर 4,771 किए जाने पर कार्य किया जा रहा है। आईसीयू बेडस् में बच्चों के लिए 320 आईसीयू (पीआईसीयू) बेडस् 20 जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध हैं। सितंबर तक सभी 51 जिला चिकित्सालयों में 520 बच्चों के आईसीयू (पीआईसीयू) बेडस् किए जाएंगे। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में 380 अतिरिक्त नवीन पीआईसीयू सितंबर 2021 तक बनाए जाएंगे। लोक स्वास्थ्य संस्थाओं में वर्तमान में 992 पीडिएट्रिक ऑक्सीजन सर्पोटेड बेड और मेडिकल कॉलेज में 300 अतिरिक्त पीडिएट्रिक बेड स्थापित करने की प्रक्रिया प्रचलित है। इसे सितंबर तक पूरा किया जाएगा। कोविड-19 महामारी संक्रमण के तेजी से बढ़ने पर और गंभीर स्थिति से संक्रमित मरीज के उपचार में वेंटीलेटर का उपयोग होता है। वर्तमान में स्वास्थ्य संस्थाओं में 2112 वेंटीलेटर उपलब्ध हैं। इनमें अतिरिक्त 161 वेंटीलेटर केवल पीडिएट्रिक और नवजात शिशुओं के लिये उपलब्ध हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कोविड संक्रमित मरीजों को और अन्य बीमारियों के मरीजों को अस्पताल लाने के लिए चिकित्सकीय उपकरणों और स्टाफ से लैस 108 एम्बूलेंस की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। अभी 600 से अधिक एम्बुलेंस संचालित हैं। अक्टूबर से 1002 एम्बुलेंस संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार प्रदेश में संचालित 820 जननी एक्सप्रेस की संख्या को अक्टूबर में बढ़ाकर 1050 करने का भी निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। स्वास्थ्य संस्थाओं में अन्य चिकित्सकीय उपकरणों, इन्फ्रॉस्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अन्य कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए भी प्रयास जारी हैं। कोविड-19 महामारी से बचाव में टीकाकरण का महत्वपूर्ण योगदान है।

» ग्राम संवादः जमीन स्तर पर समस्याओं को हल करने की सार्थक पहल

» अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने कलेक्टर और जिपं सीईओ के प्रयास

साहब पहुंचे गावं, निपटाईं समस्याएं पंचायत भवन में किया रात्रि विश्राम

सतीश साहू, बैतूल

ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत समस्याओं से रू-ब-रू होकर उनका सार्थक हल निकालने के उद्देश्य से जिले में प्रारंभ किए गए ग्राम संवाद अभियान के तहत गत दिवस कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस और जिला पंचायत सीईओ अभिलाष मिश्रा भैंसदेही विकासखंड के धाबा (सावलमेंढा) क्लस्टर पहुंचे। उन्होंने यहां रात्रि विश्राम कर क्लस्टर अंतर्गत आने वाली दस ग्राम पंचायतों की समस्याएं सुनीं। साथ ही उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। जो समस्याएं मौके पर ही हल हो सकती थीं, उनको वहीं पर निपटाया। ग्राम संवाद के दौरान ग्राम कोथल कुंड के दिव्यांग श्याम पिता नेहरू को मौके पर ही निःशक्त पेंशन स्वीकृत की गई। ग्राम पाटोली में खराब ट्रांसफार्मर तत्काल सुधार दिया गया। ग्राम पंचायत कोथलकुंड अंतर्गत सालईढाना में उचित मूल्य की दुकान नहीं खुलने की शिकायत मिलने व सेल्समेन के उपस्थित नहीं होने पर उक्त सेल्समेन को सेवा से पृथक करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए।

ग्रामीणों से सीधा संपर्क

ग्राम संवाद के अंतर्गत क्लस्टर की दस ग्राम पंचायतों डेडवाकुंड, खोमई, पिपलनाकलां, थपोड़ा, बानूर, जामुलनी, सांवलमेंढा, उदामा, कोथलकुंड एवं धाबा के ग्रामों में सुबह से ही सेक्टर अधिकारी एवं मैदानी अमला भ्रमण पर निकले। यहां उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संपर्क किया। उनकी समस्याएं और शिकायतें दर्ज की, छोटी-मोटी शिकायतों को भ्रमण के दौरान ही निराकृत किया।

विकास कार्यों का निरीक्षण

रात्रि विश्राम के बाद सुबह कलेक्टर और जिपं सीईओ क्षेत्र के विकास कार्यों के निरीक्षण पर भी निकले। इस दौरान उन्होंने सड़ड खराब होने की शिकायत के आधार पर कोथलकुंड से उदामा प्रधानमंत्री सड़क का निरीक्षण किया। सड़क सामान्य तौर पर ठीक पाई गई। जहां मरम्मत की आवश्यकता है, वहां मरम्मत के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के अधिकारी को निर्देशित किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने यहां आयुर्वेदिक औषधालय के निर्माणाधीन भवन का भी निरीक्षण किया। साथ ही समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के संबंधित एजेंसी को निर्देश दिए।

अफसरों ने देखी 'मां की बगिया'

ग्राम पंचायत विजयग्राम पहुंचकर कलेक्टर और जिपं सीईओ ने यहां तैयार की गई मां की बगिया देखी और वाटर हार्वेस्टिंग कार्य का निरीक्षण किया। झल्लार के रामजी ढाना में पशु चिकित्सा विभाग द्वारा तैयार सात मुर्गी पालन केन्द्रों का निरीक्षण करते हुए इन हितग्राहियों से चर्चा भी की। झल्लार में मनरेगा अंतर्गत तैयार किए गए खरीदी केंद्र चबूतरा निर्माण का भी निरीक्षण किया गया।

शिक्षा की भी टटोली नब्ज

ग्रामीण क्षेत्रों की सामान्य समस्याएं भी जानी ओर यहां बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, शिक्षा व्यवस्था की स्थिति की भी पड़ताल की। शाम 4 बजे कलेक्टर और सीईओ द्वारा धाबा में आयोजित ग्राम चौपाल एवं अधिकारियों की मीटिंग के दौरान सेक्टर अधिकारी, ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों की मौजूदगी में प्राप्त एक-एक शिकायत और समस्या पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान बानूर में बिजली के तार ठीक करने संबंधी समस्या, पेयजल की सुचारू उपलब्धता के लिए कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए गए। इस ग्राम पंचायत के बुरहानपुर क्षेत्र में जल संरक्षण के कार्य प्रारंभ करने के लिए भी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सहायक यंत्री को निर्देश दिए।

सरकारी भवन में शिफ्ट हो राशन दुकान

ग्राम में सामाजिक सहायता पेंशन के लंबित प्रकरणों का पात्रतानुसार तत्काल निराकरण के लिए निर्देशित किया गया। ग्राम पाटोली में उचित मूल्य की दुकान का भवन नहीं होने पर दुकान को किसी अन्य शासकीय भवन में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए। ग्राम थपोड़ा में ज्यादा क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाने की मांग पर बिजली विभाग को परीक्षण करने के निर्देश दिए गए। निघोरा में उचित मूल्य की दुकान की छत टपकने की शिकायत मिलने पर मरम्मत के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया। वहीं यहां आंगनबाड़ी भवन के अपूर्ण कार्य को एक महीने में पूरा करने के लिए संबंधित एजेंसी को निर्देश दिए गए।

गंदगी फैलाने वालों से वसूलो जुर्माना

ग्राम में गंदगी की शिकायत मिलने पर यहां स्वच्छता अभियान चलाने एवं गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना करने के संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए गए। यहां स्कूल के शौचालय की मरम्मत व साफ-सफाई के लिए विभागीय अधिकारियों को कहा गया। ग्राम साकली में मोक्षधाम तक पक्का रोड नहीं होने की शिकायत पर यहां मनरेगा से रोड बनाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। यहां के प्राथमिक शाला में शौचालय नहीं होने की जानकारी मिली, जिस पर भी शौचालय बनवाने के लिए कलेक्टर द्वारा सीईओ जनपद को निर्देश दिए गए।

पंचायत भवन में रात्रि विश्राम

ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं से वास्तविक रूप से रू-ब-रू होने के दृष्टिगत कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस और जिला पंचायत सीईओ अभिलाष मिश्रा ने ग्राम पंचायत धाबा के पंचायत भवन में रात्रि विश्राम भी किया। रात्रि विश्राम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की वास्तविकता से परिचित होना था। उन्होंने यहां प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के हितग्राही गुणवंत दुराड़ी व दुराड़ी रिंगू के निर्माणाधीन आवास भी देखे और उनसे चर्चा की। इसके अलावा ग्रामीणों से अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता पर भी उन्होंने चर्चा की।

ग्राम संवादः265 आवेदन मिले

ग्राम संवाद के दौरान विभिन्न समस्याओं पर आधारित 265 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 86 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया, शेष के निराकरण के लिए अधिकारियों को समय-सीमा दी गई। उक्त आवेदन पंजी में दर्ज कर कलेक्टर की समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। इनकी नियमित समीक्षा कर निराकरण की पहल की जाएगी।

सभी देशवसियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्री जसरथ जाटव
सरपंच
श्री ज्ञानी शर्मा — सचिव
अमर सिंह जाटव — रोज सहायक
ग्राम पंचायत रहरगुवां जनपद पंचायत करैरा जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्रीमती सुमंत जाटव पत्नी श्री सुगर सिंह जाटव
सरपंच
श्री गोपाल लोधी — सचिव
श्री अतर सिंह लोधी — रोज सहायक
ग्राम पंचायत सलैया करैरा जनपद पंचायत करैरा जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्री करण सिंह आदिवासी
सरपंच
श्री रामसेवक लोधी — सचिव
ग्राम पंचायत सिल्लारपुर जनपद पंचायत करैरा जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्रीमती मीना गुर्जर पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह गुर्जर
सरपंच
श्री प्रीतम पाल — सचिव
श्री बीरवल कुशवाह — रोज सहायक
ग्राम पंचायत शिलानगर जनपद पंचायत करैरा जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री रामेश्वर सोनी
सरपंच
श्री दिनेश बघेल — सचिव
हरप्रसाद जाटव — रोज सहायक
ग्राम पंचायत फतेहपुर जनपद पंचायत नरवर जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्री बादाम सहरिया
सरपंच
श्री रामजीलाल बघेल — सचिव
श्री रविन्द्र रावत — रोज सहायक
ग्राम पंचायत कैरुआ जनपद पंचायत नरवर जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्री ज्ञानेन्द्र बुंदेला
सरपंच
श्री राजेन्द्र तोमर — सचिव
राकेश पाल — रोज सहायक
ग्राम पंचायत सलैया डामरौन जनपद पंचायत करैरा जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्रीमती असरफी पत्नी श्री मेघसिंह जाटव
सरपंच
श्री भागीरथ कोली — सचिव
श्री देवेन्द्र राजपूत — रोज सहायक
ग्राम पंचायत ग्वालिया जनपद पंचायत नरवर जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्री मति हरकुमर
सरपंच
श्री मुकेश रावत — सचिव
श्री मनीराम जाटव — रोज सहायक
ग्राम पंचायत डुमघना जनपद पंचायत करैरा जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्रीमती पार्वती पाल पत्नी श्री वीरन पाल
सरपंच
श्री उमाशंकर भार्गव — सचिव
श्री मति नीतू राजा चौहान — रोज सहायक
ग्राम पंचायत चन्दावनी जनपद पंचायत पिछोर जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्री राजू जाटव
सरपंच
श्री राजेन्द्र सिंह कुशवाह — सचिव
श्री कैलाश गौतम — रोज सहायक
ग्राम पंचायत रामनगर(गधाई) जनपद पंचायत नरवर जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्री कोमल आदिवासी
सरपंच
श्री जानकी लाल धाकड़ — सचिव
श्री मोहर सिंह लोधी — रोज सहायक
ग्राम पंचायत चमरौआ जनपद पंचायत खनियाधाना जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्री महावीर राय
सरपंच
श्री गोवर्धन कुशवाह — सचिव
श्री कमल किशोर जाटव — रोज सहायक
ग्राम पंचायत वीरा जनपद पंचायत पिछोर जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्रीमती फूलवती लोधी पत्नी श्री सिंग्राम सिंह लोधी
सरपंच
श्री जगदीश प्रसाद लोधी — सचिव
श्री जितेन्द्र सिंह लोधी — रोज सहायक
ग्राम पंचायत छिरवाहा जनपद पंचायत पिछोर जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्री देवेन्द्र सिंह परमार
सरपंच
श्री कृष्ण पाल सिंह — सचिव
श्री मति अर्पिता गुप्ता — रोज सहायक
ग्राम पंचायत नावली जनपद पंचायत पिछोर जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

अपील-
जंगलों को आग से बचाएं
अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं
वन प्राणियों की सदैव रक्षा करे
हरे भरे पेड़ो को न काटें।

श्री अनुराग तिवारी
रेंजर

वन परिक्षेत्र करैरा, पिछोर जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्री जसवंत सिंह लोधी
सरपंच

श्री बद्री प्रसाद लोधी
सचिव

श्री सुनील शर्मा
रोज सहायक

ग्राम पंचायत बघरवारा जनपद पंचायत खनियाधाना जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्री हरविलास जाटव
सरपंच

श्री सोन सिंह जाटव
सचिव

श्रीमति प्रियंका गुप्ता
रोज सहायक

ग्राम पंचायत अमरपुर देवरा जनपद पंचायत खनियाधाना जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्री रामकुमार शर्मा
सरपंच

प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था खोड़
तहसील पिछोर जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

समस्त- कृषि सहकारी संस्था खोड़ मण्डल की ओर से

सभी देशवसियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्री मती मक्खो बाई
सरपंच

श्री रामस्वरूप बघेल
सचिव

श्री रुप सिंह कुशवाह
रोज सहायक

ग्राम पंचायत कठेंगरा जनपद पंचायत नरवर जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्रीमति गुड्डी बाई
पति श्री संतोष आदिवासी
सरपंच

श्री सिंग्राम सिंह लोधी
सचिव

ग्राम पंचायत विजरावन जनपद पंचायत खनियाधाना जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्री मती लक्ष्मी बाई बघेल
सरपंच

श्री देवीसिंह कुशवाह
सचिव

श्री नीतू रावत
रोज सहायक

ग्राम पंचायत खडीचा जनपद पंचायत नरवर जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्रीमती गीता रावत
पत्नी श्री अशोक रावत
सरपंच

श्री मनोहर रावत
सचिव

ग्राम पंचायत दिहायला जनपद पंचायत नरवर जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्रीमति फूलवती कुशवाह
सरपंच

श्री कुंवर लाल धनोलिया
सचिव

ग्राम पंचायत चकरामपुर जनपद पंचायत नरवर जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्री मती कुसुम वाई जाटव पति श्री संतोष जाटव
सरपंच

श्री अवदेश वैश्य
सचिव

श्री रामकुमार कोली
रोज सहायक

ग्राम पंचायत कोंडर जनपद पंचायत नरवर जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश।

सभी देशवसियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्रीमती रेखा शर्मा पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा
सरपंच

श्री कालूराम लोधी
सचिव

श्री दीपक गुप्ता
रोज सहायक

ग्राम पंचायत नागुली जनपद पंचायत पिछोर जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्री रघुनाथ सिंह गुर्जर
सरपंच

श्री बनवारी लाल शाक्य
सचिव

श्री धर्मेन्द्र गुर्जर
रोज सहायक

ग्राम पंचायत ठाटी जनपद पंचायत नरवर जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सभी देशवसियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्री मती मीरा बघेल
पत्नी श्री सीताराम बघेल
सरपंच

श्री संजीव कुसमरिया
सचिव

श्री अशोक लोधी
रोज सहायक

ग्राम पंचायत पारागढ़(जयनगर) जनपद पंचायत करैरा जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सौजन्य से- श्री रमेश कुमार जाटव

सभी देशवसियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्री लक्ष्मीनारायण शिवहरे
ठेकेदार

श्री रविन्द्र शिवहरे नगर पालिका अध्यक्ष कोलारस
ठेकेदार

देशी शराब कम्पनी खोड तहसील पिछोर जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

सौजन्य से- श्री जगन पाल

सभी देशवसियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्री मति मीना लोधी
सरपंच

श्री हनुमंत लोधी
सचिव

इन्दर सिंह परिहार
रोज सहायक

ग्राम पंचायत मछावली जनपद पंचायत करैरा, जिला शिवपुरी मध्य-प्रदेश

"सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा
हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा"

75 आज़ादी का अमृत महोत्सव

स्वाधीनता दिवस पर
प्रदेशवासियों को
हार्दिक
शुभकामनाएं

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

आज़ादी की वर्षगांठ पर अपने प्राणों का
उत्सर्ग करने वाले असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों को
हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं,
प्रदेश में सौहार्दपूर्ण सम-समाज और
आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण का
अपना संकल्प दृढ़ता से दोहराते हैं।

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

चुनौतियों से लड़कर देता जीत का संदेश – स्वस्थ, समृद्ध आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश

हर गरीब का अपना घर
- प्रधानमंत्री आवास योजना की 2484 करोड़ रुपये की राशि जारी।

गर्व से कर रहे खुद का व्यवसाय
- पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 3 लाख 16 हजार शहरी पथ विक्रेताओं को मिला 316 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण।

आजीविका के अवसर
- प्रदेश में 5 लाख 54 हजार परिवारों को आजीविका स्व-सहायता समूहों से जोड़कर 4% ब्याज पर 1 हजार 400 करोड़ रुपये का बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया।

हर कदम अन्नदाता के साथ
- कोरोना काल में रबी विपणन वर्ष 2021-22 में 17.16 लाख किसानों से 128.16 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर किसानों को 25,000 करोड़ रुपये का भुगतान।
- विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं के माध्यम से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के हितलाभ किसानों को दिये गये।

सबको भोजन और पोषण
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 7 अगस्त को अन्नोत्सव में 1 करोड़ 15 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण।

स्वास्थ्य पर ध्यान
- अब तक 2.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी। 8 लाख 50 हजार हितग्राहियों का करीब 1200 करोड़ रुपये के व्यय से निःशुल्क इलाज।

खेलों को प्रोत्साहन
- खेलो इण्डिया योजना के अंतर्गत प्रदेश में 3 बड़े खेल सेंटर और 10 छोटे खेल सेंटर मंजूर।
- टोक्यो ओलम्पिक 2021 में मध्यप्रदेश के 11 खिलाड़ियों द्वारा देश का प्रतिनिधित्व।

महिला सशक्तिकरण
- प्रदेश के सभी जिलों के 700 थानों में ऊर्जा महिला डेस्क की स्थापना।
- महिलाओं के लिये ₹ 100 करोड़ की लागत से नारी सम्मान कोष की स्थापना।
- धार्मिक स्वतंत्रता कानून 2020 लागू।

कोरोना संक्रमण प्रभावितों की मदद के कदम
- कोविड आपदा में निराश्रित बच्चों की मदद के लिये मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना।
- कोविड आपदा में शासकीय कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख रुपये की वित्तीय मदद।
- मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत शासकीय कर्मचारी की मृत्यु होने पर एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति।
- कोविड-19 ड्यूटी पर तैनात फ्रंट लाइन वर्कर की मृत्यु हो जाने पर परिवार को 50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता।
- मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना में आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों को निःशुल्क कोविड उपचार की सुविधा।

D18069/21

प्रेरणा और प्रगति का प्रदेश मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **सतीश उपाध्याय, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)